ई संदेश

22 जनवरी, 2026 | अंक -189

सात दिन सात पृष्ठ

जनपद चंदौली में एकीकृत न्यायालय परिसर की आधारशिला रखने के अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकान्त जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

- खेल और उससे जुड़ी गतिविधियां हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आयाम: मुख्यमंत्री
- उ0प्र0 को केवल निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता का केंद्र बनाया जाए : मुख्यमंत्री
- प्रदेश का प्रत्येक जनपद अपने विशिष्ट स्वाद, संस्कृति और पहचान के साथ सामने आए : मुख्यमंत्री
- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में जनपद चन्दौली में एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया
- प्रदेश सरकार ने विगत 08-09 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की : मुख्यमंत्री
- प्रदेश में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की सम्भावनाएँ तेजी से आगे बढ़ी हैं : मुख्यमंत्री
- लोक सभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री उ0प्र0 विधान सभा में देश के विधायी निकायों के 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में सम्मिलित हुए

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

खेल और उससे जुड़ी गतिविधियां हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आयाम: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 16 जनवरी, 2026 को दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र अन्तर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (महिला) प्रतियोगिता 2025-26 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं शहीद नन्द कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ के बीच हुए मैच का अवलोकन तथा विश्वविद्यालय की खेल पत्रिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र अन्तर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (महिला) प्रतियोगिता 2025-26 के आयोजन के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रति आभार प्रकट किया। पांच दिवसीय इस प्रतियोगिता में 14 राज्यों के 31 विश्वविद्यालयों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में खेल और उससे जुड़ी गतिविधियां हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आयाम बन चुकी हैं। भारत की प्राचीन परम्परा ने खेलकूद की गतिविधियों को सदैव महत्व दिया है। खेलकूद की गतिविधियों को केवल औपचारिकता न समझें, बल्कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2014 के बाद देश में नई खेल संस्कृति विकसित की है। उन्होंने 'खेलो इण्डिया' तथा 'फिट इण्डिया मूवमेण्ट' के माध्यम से देशवासियों को स्वस्थ शरीर से सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार करने की प्रेरणा प्रदान की। सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से गांव-गांव तक खेल भावना का प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज अनेक परिवारों ने खेलकूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। अभिभावक बच्चों को पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ खेल के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं तथा उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अभिभावकों की इस प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर खेल सम्बन्धित इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, ग्राम पंचायत व नगर निकाय में ओपन जिम, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम तथा जनपद स्तर पर स्टेडियम के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड तथा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भारत सरकार के साथ विभिन्न राज्य सरकारें भी पुरस्कृत करती हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अब तक ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड तथा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले 500 से अधिक खिलाड़ियों को डिप्टी एस0पी0, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आदि पदों पर नियुक्त किया गया है। आने वाले समय में जो युवा इन प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करेंगे, उन्हें भी इस कार्यवाही के साथ जोड़ा जाएगा। प्रदेश में गाँवों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 96,000 युवक एवं महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करायी गई है। किसी भी अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीत कर लाने वाली टीम के साथ प्रधानमंत्री जी स्वयं इण्टरेक्शन करते हैं। जब कोई भारतीय टीम प्रतिभाग करने जाती है, तो उसे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हर प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश के अहमदाबाद शहर में वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। इस आयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि की टीमों को स्वयं को अभी से तैयार करना होगा। जो आज से खेल में आगे बढ़ेगा, वह वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई करेगा और मेडल जीतेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने विगत दिनों देश में आयोजित अनेक इण्टर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर मेडल प्राप्त किए हैं। सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय कम से कम एक खेल को गोद लेकर अच्छे खिलाड़ियों को तराशने का काम करें। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाएं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाएं हमें जीवन के प्रति भी अनुशासित बनाएगी तथा खेल भावना को और अधिक सुदृढ़ करेंगी। यदि हमारा युवा खेलकूद की गतिविधियों में आगे बढ़ेगा तो नशे से दूर तथा विकृतियों से बचा रहेगा। तभी हम विकसित भारत/2047 के लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारम्भ करते हुए मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के अन्तर्गत मेरठ में निर्मित खेल सामग्रियों की देश व दुनिया में मांग बढ़ी है।

इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायकगण एवं विधान परिषद सदस्य, गोरखपुर के महापौर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती पूनम टण्डन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 17 जनवरी 2026 को जनपद गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित पांच दिवसीय पूर्वी क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया।

झलकियां

उ0प्र0 को केवल निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता का केंद्र बनाया जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 16 जनवरी, 2026 को यहां लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में औद्योगिक विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने हेतु 'सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन' कार्ययोजना की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को केवल निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता का केन्द्र बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 'सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन' मॉडल जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बने।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विकसित होने वाला यह जोन इण्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट ईको-सिस्टम के रूप में कार्य करे, जहां उद्योग, प्रशिक्षण और सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित होने के साथ-साथ युवाओं को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और उद्यमिता से जोड़ना इस परियोजना का मूल उद्देश्य है।

बैठक में बताया गया कि योजना के तहत प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल में यह ज़ोन विकसित किया जाएगा। हर ज़ोन में जी$3 भवन में 'सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र' स्थापित किया जाएगा, जो रोजगार, प्रशिक्षण और कॉमन फैसिलिटी सेंटर के रूप में कार्य करेगा। रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र में ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के लिए डिस्प्ले जोन, प्रशिक्षण हॉल, मीटिंग सुविधाएं, जिला उद्योग केंद्र, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जिला रोजगार कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर और बैंकिंग सुविधा आदि शामिल होंगे।

यह केंद्र युवाओं और उद्यमियों के लिए वन-स्टॉप सपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। औद्योगिक जोन का डिजाइन 'प्लग एंड प्ले' मॉडल पर आधारित होगा। इससे एम0एस0एम0ई0 सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उद्योगों को तुरंत संचालन की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जोन के साथ स्किलिंग, हैंडहोल्डिंग और प्लेसमेंट सेवाओं को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सेवा और उद्योग क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल उन्नयन, रोजगार मेलों, उद्यमिता प्रशिक्षण और मेंटरिंग के माध्यम से युवाओं को सीधे उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने इस सम्बन्ध में सभी जनपदों में आवश्यक भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह परियोजना ओ0डी0ओ0पी0, एम0एस0एम0ई0 और कौशल विकास योजनाओं के साथ समन्वय बनाकर लागू की जाए, ताकि स्थानीय उत्पादों, उद्योगों और युवाओं को एक साझा मंच मिले। उन्होंने नियमित समीक्षा, स्पष्ट टाइमलाइन और जमीनी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।

मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि 'सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन' प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा और उत्तर प्रदेश को रोजगार-आधारित विकास मॉडल के राष्ट्रीय उदाहरण के रूप में स्थापित करेगा।

प्रदेश का प्रत्येक जनपद अपने विशिष्ट स्वाद, संस्कृति और पहचान के साथ सामने आए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण खान-पान परम्परा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओ0डी0ओ0सी0) योजना के शुभारम्भ का निर्णय लिया है। 16 जनवरी, 2026 को यहाँ लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओ0डी0ओ0सी0) योजना के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक जनपद अपने विशिष्ट स्वाद, संस्कृति और पहचान के साथ सामने आए, यही ओ0डी0ओ0सी0 योजना का मूल उद्देश्य है।ब्राण्ड यू0पी0 को सशक्त बनाने में एक जनपद-एक उत्पाद योजना की बड़ी भूमिका के बाद अब उत्तर प्रदेश की पारम्परिक कुज़ीन को संगठित ब्राण्डिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओ0डी0ओ0सी0 योजना 'वोकल फॉर लोकल' को नई गति देने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की पाक कला की विरासत को वैश्विक फूड मैप पर स्थापित करेगी। यह पहल केवल योजना न रहकर, प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन का मजबूत माध्यम बने, इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद मैनपुरी की सोनपापड़ी, मथुरा का पेड़ा, अलीगढ़ की चमचम, हाथरस की रबड़ी, कासगंज का कलाकंद और मूंग का दलमा, एटा की चिकोरी, सुल्तानपुर की कड़ाहा की पूरी और कोहड़े की सब्ज़ी, बाराबंकी की चन्द्रकला मिठाई, आज़मगढ़ का सफ़ेद गाजर का हलवा, वाराणसी की लौंगलता, बरेली की सिंवइयां, अमेठी का समोसा, बस्ती का सिरका और सिद्धार्थनगर की रामकटोरी जैसी पारम्परिक मिठाइयाँ और व्यंजन केवल भोजन नहीं, बल्कि स्थानीय विरासत, कौशल और आर्थिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें गुणवत्ता, पहचान और बाज़ार उपलब्ध कराकर प्रदेश की सांस्कृतिक ताकत को आर्थिक शक्ति में बदला जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओ0डी0ओ0सी0 को ओ0डी0ओ0पी0 की तर्ज पर जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, ताकि पारम्परिक कारीगरों, हलवाइयों और छोटे उद्यमियों को स्थायी आजीविका के अवसर मिलें। गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और सभी उत्पादों को खाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया जाए। उन्होंने जी0आई0 टैगिंग को प्रोत्साहित करने, स्थानीय व्यंजनों की पहचान सुरक्षित रखने और युवाओं व आधुनिक उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार स्वाद-आधारित विविधता विकसित करने पर भी बल दिया। ओ0डी0ओ0सी0 के तहत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट व्यंजनों की पहचान कर उन्हें कुज़ीन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाए। पारम्परिक व्यंजनों की ब्राण्डिंग, टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए निर्माताओं और विक्रेताओं को प्रोत्साहन दिया जाए।

मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि ओ0डी0ओ0सी0 योजना के अन्तर्गत उत्पादों के संरक्षण, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, खाद्य विविधता का विस्तार, रोजगार सृजन, वैल्यू-चेन और मार्केट लिंकेज को मजबूत करना तथा पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ एकीकरण शामिल है। साथ ही, निर्यात क्षमता बढ़ाने और अन्तरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों को तैयार करने की रणनीति पर भी कार्य किया जाएगा। ब्राण्डिंग रणनीति के तहत ओ0डी0ओ0सी0 'लोगो' के साथ जनपद-विशिष्ट रंग, प्रतीक और शैली जोड़ी जाएगी। हर व्यंजन के साथ उसकी संस्कृति, इतिहास और विधि को दर्शाने वाली प्रोडक्ट स्टोरी और पहचान टैग शामिल होगा।

बैठक में मुख्यमंत्री जी को यह भी अवगत कराया गया कि पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फूड-ग्रेड, ईको-फ्रैण्डली और सुरक्षित पैकेजिंग के साथ शेल्फ-लाइफ बढ़ाने की उन्नत तकनीकों का उपयोग होगा। क्यू0आर0 कोड, न्यूट्रिशन लेबल, बारकोड और ड्यूल-लैंग्वेज लेबलिंग के माध्यम से ट्रेसेब्लिटी और उपभोक्ता जानकारी सुनिश्चित की जाएगी। क्षेत्रीय और त्योहार-थीम आधारित पैकेजिंग डिजाइनों को भी विकसित किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में जनपद चन्दौली में एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी ने जनपद चंदौली में 17 जनवरी, 2026 को एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। चंदौली में संपन्न इसी कार्यक्रम से जनपद महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस तथा औरैया में वर्चुअल माध्यम से सम्पन्न किया गया।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकान्त जी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये कहा कि यह क्षेत्र बाबा स्वामीनाथ व अनेक ऐतिहासिक तथा धार्मिक मन्दिरों के लिये प्रसिद्ध है। इस स्वर्णिम इतिहास में आज मुख्यमंत्री जी ने एक नयी कड़ी जोड़ी है, जब यहाँ न्यायिक मन्दिरों की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने 10 इन्टीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की घोषणा की, जिनमें से आज 06 का शिलान्यास किया जा रहा है। इस कार्य से उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश में एक एक्जाम्पल सेट करेगा। यह इन्टीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स सम्पूर्ण भारत के लिये बेंचमार्क बनेंगे। जिस प्रदेश में जाऊँगा, खुशी व गर्व के साथ उत्तर प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत करें, वहाँ की राज्य सरकारों से यह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आह्वान करूंगा।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इन्टीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स आगामी 50 वर्षों तक न्याय परिसर की आवश्यकतायें सशक्त रूप से पूर्ण करने में सफल होंगे। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों के साथ-साथ न्याय की खोज में आये आम आदमी को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना सराहनीय कदम है। इस कार्य के लिये उत्तर प्रदेश सरकार एवं उच्च न्यायालय बधाई के पात्र हैं। भारत के संविधान में डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संविधान निर्माताओं का मानना रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशयरी स्थापित होने से देश में एक्सेस टू जस्टिस का सपना पूरा होगा। लोगों को नजदीक से नजदीक कोर्ट की सुविधाएं प्राप्त होंगी, जहाँ वह अपने अधिकारों के लिये लड़ सकेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण हेतु न्यायपालिका का सशक्त होना तथा कॉमनमैन को सहजता से न्याय उपलब्ध कराने के लिये न्यायिक व्यवस्था से सम्बन्धित अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर होना आवश्यक है। सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये न्यायिक सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये प्रदेश सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग के लक्ष्य के प्राप्ति हेतु अनेक रिफॉर्म किये तथा देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए। देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकान्त जी ने अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान उल्लेख किया था कि प्रत्येक नागरिक को सहजता से न्याय उपलब्ध कराने के लिये एक इन्टीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मॉडल कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा तथा न्यायमूर्ति श्री सूर्यकान्त जी के सुझाव को ध्यान को रखते हुये आज प्रदेश में न्याय पालिका के इतिहास के एक नये पृष्ठ का सृजन हो रहा है। श्री काशी विश्वनाथ तथा बाबा कीनानाथ की पावन धरा चंदौली सहित 06 जनपदों में एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया जा रहा है। जनपद चन्दौली में भौतिक रूप से तथा जनपद महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस तथा औरैया में वर्चुअल माध्यम से यह कार्य सम्पन्न हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के ऐसे 10 जनपदों में जहां अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाये थे, वहाँ इन्टीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की स्वीकृति प्रदान की। चन्दौली सहित 06 जनपदों में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु सारी औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं। आज यहाँ देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन किये जाने के पश्चात एल0 एण्ड टी0 जैसी विश्व विख्यात संस्था द्वारा शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इन्टीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में न्यायिक अधिकारियां के लिये आवासीय सुविधा, अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर, पार्किंग, कैंटीन तथा स्पोर्ट्स परिसर आदि व्यवस्थायें की जायेंगी। 04 अन्य जनपदों में इन्टीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु अगले कुछ महीनों औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये कार्य आगे बढ़ाया जायेगा।

प्रदेश सरकार ने विगत 08-09 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी18 जनवरी, 2026 को यहां लखनऊ में यू0पी0 हेल्थटेक कॉन्क्लेव-1.0 के शुभारम्भ कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने बटन दबाकर इण्टीग्रेटेड मेडिकल रिसर्च एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर (यू0पी0 इमरास) को लॉन्च तथा 'स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटीज' पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के साथ ही आस-पास के राज्यों और पड़ोसी देश की भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश पर आता है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर विगत 08-09 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने का प्रयास किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर कुल 40 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज 81 मेडिकल कॉलेज पूरी तरह क्रियाशील हैं। दो एम्स के साथ ही, जिला स्तर के 100 से अधिक हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं। सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 और हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर की लम्बी श्रंखला के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।विगत 11 वर्ष में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत अकेले उत्तर प्रदेश में 05 करोड़ से अधिक आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी किए गये हैं, जिन्हें योजना के माध्यम से 05 लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य कवर की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। जो व्यक्ति आयुष्मान कार्ड की सुविधा की पात्रता श्रेणी में आता और उसे कार्ड प्राप्त नहीं हुआ, उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर किया गया है। 25 करोड़ की आबादी में अन्य लोगों के लिए भी सुविधा है। सभी के लिए मेडिकल कॉलेजों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त व बिना भेदभाव उपलब्ध करवायी जाती है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप मातृ व शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने तथा संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में सफलता मिली है। प्रदेश के कई जनपदों में ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता मिली है। पहले प्रदेश में वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लम्बी श्रृंखला देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद मानसून आते ही, अलग-अलग क्षेत्रों में इंसेफेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया व कालाजार के मामले देखने को मिलते थे। इंसेफेलाइटिस से 40 वर्षों में 50 हजार बच्चों की मौत हुई थी। वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले दो वर्षों में ही इंसेफेलाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गया। प्रदेश में आज इंसेफेलाइटिस के कारण जीरो डेथ है। प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, कालाजार व चिकनगुनिया को पूरी तरह नियंत्रित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के 'ईज़ ऑफ लिविंग' के लक्ष्य को प्राप्त करने व प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन एवं स्वस्थ दिनचर्या के लिए अभी लम्बी दूरी तय करनी है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 'ईज़ ऑफ लिविंग' और सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नए कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसके अन्तर्गत यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई युद्धस्तर पर आगे बढ़ी है। जनपद ललितपुर में प्रमोट फार्मा पार्क विकसित हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके स्वयं के स्मार्टफोन या टूल के माध्यम से सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने में सहयोग हो सकता है। स्क्रीनिंग की यह प्रक्रिया हम अन्तिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारम्भ कर सकते हैं, जिससे गांव में बैठे हुये व्यक्ति को बहुत दूर न जाना पड़े, बल्कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने इंसेफेलाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि इंसेफेलाइटिस के पेशेंट को समय पर डिटेक्ट करके उसका लोकल सेंटर में उपचार किया गया। उपचार के लिए उसे दूर नहीं जाना पड़ा। नजदीकी पी0एच0सी0 या हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में ही उपचार की सुविधा प्राप्त हुयी। यह प्रक्रिया सख्ती से लागू की गई और यह तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में कोई भी पेशेंट आता है, तो यह पता लगना चाहिए कि किस गांव से आया है और उसकी बी0एस0टी0 लिखी जानी चाहिए कि किस डॉक्टर ने उसको रिफर किया है। वर्करों को ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। इसके परिणामस्वरूप मात्र 02 वर्ष में 40 वर्ष में महामारी बन चुकी एक बीमारी को नियंत्रित कर लिया गया। यह टेक्नोलॉजी से सम्भव है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी18 जनवरी, 2026 को यहां लखनऊ में यू0पी0 हेल्थटेक कॉन्क्लेव-1.0 के शुभारम्भ कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने बटन दबाकर इण्टीग्रेटेड मेडिकल रिसर्च एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर (यू0पी0 इमरास) को लॉन्च तथा 'स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटीज' पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के साथ ही आस-पास के राज्यों और पड़ोसी देश की भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश पर आता है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर विगत 08-09 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने का प्रयास किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर कुल 40 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज 81 मेडिकल कॉलेज पूरी तरह क्रियाशील हैं। दो एम्स के साथ ही, जिला स्तर के 100 से अधिक हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं। सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 और हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर की लम्बी श्रंखला के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।विगत 11 वर्ष में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत अकेले उत्तर प्रदेश में 05 करोड़ से अधिक आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी किए गये हैं, जिन्हें योजना के माध्यम से 05 लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य कवर की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। जो व्यक्ति आयुष्मान कार्ड की सुविधा की पात्रता श्रेणी में आता और उसे कार्ड प्राप्त नहीं हुआ, उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर किया गया है। 25 करोड़ की आबादी में अन्य लोगों के लिए भी सुविधा है। सभी के लिए मेडिकल कॉलेजों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त व बिना भेदभाव उपलब्ध करवायी जाती है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप मातृ व शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने तथा संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में सफलता मिली है। प्रदेश के कई जनपदों में ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता मिली है। पहले प्रदेश में वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लम्बी श्रृंखला देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद मानसून आते ही, अलग-अलग क्षेत्रों में इंसेफेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया व कालाजार के मामले देखने को मिलते थे। इंसेफेलाइटिस से 40 वर्षों में 50 हजार बच्चों की मौत हुयी थी। वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले दो वर्षों में ही इंसेफेलाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गया। प्रदेश में आज इंसेफेलाइटिस के कारण जीरो डेथ है। प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, कालाजार व चिकनगुनिया को पूरी तरह नियंत्रित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के 'ईज़ ऑफ लिविंग' के लक्ष्य को प्राप्त करने व प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन एवं स्वस्थ दिनचर्या के लिए अभी लम्बी दूरी तय करनी है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 'ईज़ ऑफ लिविंग' और सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नए कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसके अन्तर्गत यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई युद्धस्तर पर आगे बढ़ी है। जनपद ललितपुर में प्रमोट फार्मा पार्क विकसित हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके स्वयं के स्मार्टफोन या टूल के माध्यम से सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने में सहयोग हो सकता है। स्क्रीनिंग की यह प्रक्रिया हम अन्तिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारम्भ कर सकते हैं, जिससे गांव में बैठे हुये व्यक्ति को बहुत दूर न जाना पड़े, बल्कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने इंसेफेलाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि इंसेफेलाइटिस के पेशेंट को समय पर डिटेक्ट करके उसका लोकल सेंटर में उपचार किया गया। उपचार के लिए उसे दूर नहीं जाना पड़ा। नजदीकी पी0एच0सी0 या हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में ही उपचार की सुविधा प्राप्त हुयी। यह प्रक्रिया सख्ती से लागू की गई और यह तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में कोई भी पेशेंट आता है, तो यह पता लगना चाहिए कि किस गांव से आया है और उसकी बी0एस0टी0 लिखी जानी चाहिए कि किस डॉक्टर ने उसको रिफर किया है। वर्करों को ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। इसके परिणामस्वरूप मात्र 02 वर्ष में 40 वर्ष में महामारी बन चुकी एक बीमारी को नियंत्रित कर लिया गया। यह टेक्नोलॉजी से सम्भव है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है।

शिष्टाचार भेंट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 21 जनवरी 2026 को राजभवन, लखनऊ में मा0 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से शिष्टाचार भेंट की।

लोक सभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री उ0प्र0 विधान सभा में देश के विधायी निकायों के 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में सम्मिलित हुए

विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर
भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर 24 घण्टे से अधिक चलने वाली
बहस में प्रदेश विधान सभा के 300 से अधिक सदस्यों ने प्रतिभाग किया

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 22 जनवरी, 2026 को यहाँ विधान सभा, लखनऊ में देश के विधायी निकायों के 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुँवर मानवेन्द्र सिंह तथा विधान सभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना भी उपस्थित थे।

लोक सभा अध्यक्ष ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हुए हैं। राज्य में सुशासन, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और ठोस कानून-व्यवस्था से बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ है तथा प्रदेश में निवेश की गति बढ़ी है। मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें नई दिशा तथा नए दृष्टिकोण के साथ नए संकल्प की ओर प्रशस्त करेगा। इस सम्मेलन में हुई सार्थक चर्चा व संवाद के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक मजबूत, जवाबदेह, उत्तरदायी तथा पारदर्शी बनाने के लिए विचार प्राप्त हुए हैं।

लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह न्यायालय में लोगों का विश्वास रहता है कि न्यायालय में उनकी बात अवश्य सुनी जाएगी। इसी प्रकार यदि राज्य विधान मण्डल में सकारात्मक दृष्टिकोण तथा सकारात्मक दिशा में जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे, तो निश्चित ही बेहतर परिणाम सामने आएंगे। विधान सभाओं को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, ए0आई0 टेक्नोलॉजी की ओर हम बढ़े हैं। आज सभी राज्य की विधान सभाएं पेपरलेस हो चुकी हैं तथा पुरानी डिबेट्स, चर्चाएं, संवाद, मुद्दे, बजट आदि को डिजिटाइज किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुये देश में न केवल विधायी कार्यों के लिये रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि यह समग्र विकास की कार्ययोजना का मंच भी होती है। विधायिका के मंच पर न्याय प्रदान करने वाले कानून का निर्माण होता है। न्याय, समता और बंधुता संविधान के यह तीन शब्द भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में कार्य करते हैं।

हमारी विधायिका का मंच समतामूलक समाज की स्थापना में योगदान देने वाली सरकार की योजनाओं से सम्बन्धित कार्ययोजना का स्थल बनता है। सहमति-असहमति के बीच समन्वय करते हुये बेहतरीन संवाद के माध्यम से विधायिका बन्धुता का उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। हमारे देश में लोकतंत्र की यह सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है। यह दुनिया के लिये एक नयी प्रेरणा है। सर्वोच्च सदन में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज को रखा जाता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नियमों तथा परिनियमों के निर्माण में 'संसद' आधार बन सकती है। 'संसद' के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना प्रत्येक भारतवासी का दायित्व बनता है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं कि भारत दुनिया के लोकतंत्र की जननी है। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था बाद में लागू की गयी, लेकिन गाँवों के सरपंच और पंचों की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। हम लोगों ने इस व्यवस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। हमारे गाँवों ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया है।

देश में रूप-रंग, वेश-भूषा अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत सभी दिशाओं में एक भाव व भंगिमा के साथ बोलता तथा सोचता है। सम्पूर्ण देश की भावना व आस्था भी एक है। संसद इस आस्था को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। यदि हम संसद के इस भाव से जुड़ते हुये उसे आदर्श के रूप में आगे बढ़ायेंगे, तो हमारी विधायिका और अधिक सशक्त व मजबूत बनेगी।

प्रधानमंत्री जी के विज़न के अनुरूप आज उ0प्र0 अपनी नई पहचान बना रहा,
मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश 'विकसित उत्तर प्रदेश@2047'
विज़न डॉक्युमेण्ट पर कार्य कर रहा : उप सभापति, राज्य सभा

इस 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में 06 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करने का अभिनन्दनीय कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना बनाने के लिये कहा। विकसित भारत@2047 की परिकल्पना को आज यहां पारित करते हुए एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उप सभापति, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति ने विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर चली लम्बी डिबेट की यहां चर्चा की है।

विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर लगातार 24 घण्टे से अधिक चलने वाली बहस में विधान सभा के 300 से अधिक सदस्यों ने प्रतिभाग किया था। सदस्यों में बोलने की होड़ लगी थी। इस परिचर्चा से विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। इस परिचर्चा के पश्चात विजन डॉक्युमेण्ट तैयार करने तथा इसमें जनता के सुझाव सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना केवल भारत सरकार व प्रधानमंत्री जी का ही काम नहीं है, बल्कि हम भी इस अभियान के सारथी व सिपाही बन सकते हैं। इस सम्मेलन में इस प्रस्ताव को पारित करते हुए प्रभावी ढंग से इसे आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ, विकसित भारत की संकल्पना को साकार बनाने की दिशा में किये गये प्रयासों को एक सार्थक गति प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा देश से जुड़े हुये ज्वलंत मुद्दों से सम्बन्धित चर्चा-परिचर्चा को अनवरत आगे बढ़ाती है। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट गोल्स से सम्बन्धित लगातार 37-38 घण्टे तक परिचर्चा हुयी थी। लक्ष्य निर्धारित करते हुये मंत्रिमण्डल तथा अलग-अलग विभागों के चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर कमेटियां गठित की गयीं। यह सभी कमेटियां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में अनवरत कार्य कर रही हैं। सदन में संविधान दिवस पर मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्तव्यों पर भी अनवरत चर्चा की गयी है। यह चर्चा केवल सदन तक सीमित नहीं रहती। विधायकों से कहा जाता है कि इसी प्रकार की चर्चा वह अपनी विधान सभा क्षेत्र में भी कराएँ।

राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने कहा कि तीन दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये। उनके अनुभव, पहल व इनोवेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति ने सभी को ऊर्जा व प्रेरणा दी है। राज्य की जी0डी0पी0, प्रति व्यक्ति आय, बजट आकार में बढ़ोत्तरी, निर्यात में वृद्धि, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रगति तथा सर्वांगीण प्रगति के आधार पर नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को फ्रण्ट रनर कहा है। उत्तर प्रदेश आज बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरता हुआ राज्य है। यह एक समय बीमारू राज्य था, जो आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यह प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है।

राज्य सभा के उप सभापति ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से वर्ष 2025 के बीच किये गये सुनियोजित प्रयासों से 06 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। साथ ही अगले 05 साल में राज्य की ग्रोथ रेट 20 प्रतिशत करने तथा वर्ष 2047 तक इसे 06 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। यदि हम इस रास्ते पर तेजी से बढ़े, तो भारत की आर्थिक ताकत बहुत अधिक हो जाएगी। इस रूप में मुख्यमंत्री जी का विज़न 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' तथा 'आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' का है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित